X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

वर्ष के दौरान, यूक्रेन में युद्ध के बाद अनिश्चितता की तीव्रता के साथ, संचार का जोर अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता पर था, और लोगों के व्यापक समूहों तक पहुंचकर प्रभावशीलता में सुधार करने का प्रयास किया गया। रिज़र्व बैंक में आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान कार्य में नीति निर्माण और संचार में सहायता के लिए व्यापक समकालीन और कार्यनीतिक मुद्दों को शामिल किया गया। सूचना प्रबंधन प्रणालियों में और सुधार किया गया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी 20 की अध्यक्षता संभाली, जहां रिज़र्व बैंक का ध्यान वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और संबंधित वितरण पर होगा। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के ठोस प्रबंधन की दिशा में भी प्रयास किए गए। एक मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विधायी पहल/संशोधन किए गए।

X.1 रिज़र्व बैंक की संचार कार्यनीति जो प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के सिद्धांतों का पालन करती है, ने अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यों के बारे में जनधारणा को प्रभावी ढंग से संभाला है। इसके अलावा, संचार के मौखिक और अनौपचारिक तरीके, जो संरचित और लिखित संचार के पूरक हैं, प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे जनता के साथ सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया, और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भारतीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। 1 दिसंबर, 2022 से, रिज़र्व बैंक भारत के जी20 की अध्यक्षता के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग से जी20 फाइनेंस ट्रैक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रह की मौजूदा प्रक्रिया को कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) 2.0 में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर संग्रह (सीमा शुल्क सहित) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (एसीएल) ढांचे को बढ़ावा दिया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में, रिज़र्व बैंक ने उस क्रम में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के व्यापक उद्देश्य के साथ काम करना जारी रखा। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक ने नीति निर्माण और संचार के लिए महत्वपूर्ण समकालीन विषयों पर अनुसंधान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, 1997-2008 की अवधि को कवर करने वाले 'भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास' के पांचवें खंड और अपने प्रमुख प्रकाशनों की समय पर रिलीज सुनिश्चित करने के अलावा पहली 'म्यूनिसिपल फाइनेंस पर रिपोर्ट' जारी करके अपने प्रकाशनों को मजबूत किया। सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस [अर्थात्, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] के विकास और गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों के उपयोग के माध्यम से और मजबूत किया गया था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली[1] जो भारतीय बैंकिंग के वितरण पहलुओं को प्रदान करती है, ने 2022 में सफलतापूर्वक संचालन के पचास साल पूरे किए। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई संशोधन/विधान भी प्रस्तुत किए गए।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। अगला खंड रिज़र्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों

[1] 1972 में आरंभ की गई , यह एक सुदृढ़ और व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली में बदल गई है, जिससे उपयोगी आंकड़ों की एक विस्तृत शृंखला प्राप्त होती है।

को प्रस्तुत करता है। अगला खंड अपनी संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ बातचीत शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण करता है। खंड 6 अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसमें वैधानिक रिपोर्ट और फ्रंटलाइन अनुसंधान प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों को रेखांकित करता है, जबकि खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 यूक्रेन युद्ध, जलवायु जोखिम और केंद्रीय बैंकों में मौद्रिक नीति की समन्वित सख्ती जैसी घटनाओं के बाद गतिशील और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर, केंद्रीय बैंकों की संचार कार्यनीति में एक विशेष बदलाव देखा गया है। केंद्रीय बैंक का संचार, जिसका लक्ष्य पहले मुख्य रूप से नीतिगत कार्यों और उनके औचित्य को व्यक्त करना था, अब इसका उपयोग तेजी से अवधारणा प्रबंधन के लिए रहा है, जो नीतियों की प्रभावशीलता में हस्तक्षेप पर बाजार की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल और अनुचित बदलाव की भूमिका की पहचान करता है। मौद्रिक और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों, विनियमन और पर्यवेक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे जटिल और तकनीकी केंद्रीय बैंकिंग विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यों से निपटने के दौरान जन-अवधारणा का प्रबंधन करना केंद्रीय बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

X.4 अधिक पारदर्शिता के लिए, मौद्रिक नीति संचार में आगामी मार्गदर्शन प्रदान करना हाल के दिनों में अधिकांश केंद्रीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण बन गया। उभरती घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ, हालांकि, कुछ केंद्रीय बैंक स्पष्ट फॉरवर्ड मार्गदर्शन देने से बच रहे हैं। इस प्रकार, मौद्रिक नीति संचार इस समय अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के माहौल के बीच बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

X.5 संरचित और लिखित संचार, जो वित्तीय बाजारों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका हुआ करता था, अब इसे भाषणों और साक्षात्कारों, अनौपचारिक मीडिया बातचीत और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर मीडिया कार्यशालाओं के संदर्भ में मौखिक संचार द्वारा पुष्ट किया जा रहा है। संचार का मौखिक और अनौपचारिक तरीका संचार के प्रभावी तरीके बन गए हैं क्योंकि ये केंद्रीय बैंक को जनता के साथ सीधे संवाद करने और अपनी नीतियों और कार्यों के पीछे के तर्क और आगामी कार्यनीति प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह दो-तरफ़ा संचार, जिसमें प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान मौके पर स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है, नया मानदंड बनता जा रहा है। भाषणों और साक्षात्कारों की भाषा गैर-तकनीकी और समझने में आसान है। अध्ययनों से पता चला है कि संचार अधिक प्रभावी होता है जब केंद्रीय बैंक सरल और भरोसेमंद भाषा का उपयोग करता है क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास बनाने और जनता की अपेक्षाओं को खरा उतरने में मदद करता है। हाल ही में, केंद्रीय बैंक प्रतिष्ठा जोखिम को कम करने, केंद्रीय बैंक के संचालन में विश्वास और भरोसा निर्माण करने और इसके पारदर्शिता प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस तरह के औपचारिक और अनौपचारिक मौखिक संचार का उपयोग कर रहे हैं।

X.6 हाल के दशकों में संचार में पारदर्शिता की भूमिका काफी बढ़ गई है। सोशल मीडिया जैसे नए युग के डिजिटल प्लेटफार्मों के आगमन के साथ यह प्रवृत्ति तेज हो गई, जिसने तेजी से और बड़े दर्शक वर्ग के बीच सूचना के प्रसार को बढ़ाया है। रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को उजागर करने, सार्वजनिक हित के नीतिगत कार्यों को अनौपचारिक और शिक्षाप्रद प्रारूप में संप्रेषित करने के लिए रिज़र्व बैंक अपने 360 डिग्री अखिल भारतीय जन जागरूकता अभियानों का भी

उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य जनता के साथ ज्यादा जुड़ना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियान (पीएसी) का व्यापक उद्देश्य टैगलाइन - आरबीआई *कहता है ... जानकार बनिये, सतर्क रहें!* (आरबीआई सेज़ ... बी अवेयर, बी एलर्ट!) के तहत धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ खुद को बचाने के बारे में ज्ञान से लैस करते हुए ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में रिज़र्व बैंक की अच्छी पद्धतियों, विनियमों और पहलों के बारे में बैंक ग्राहकों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करना था। इसके अलावा, संचार की प्रक्रिया आवधिक, कैलेंडर-आधारित और व्यवस्थित है, और इसमें सभी सामाजिक समूह शामिल हैं।

X.7 रिज़र्व बैंक सक्रिय संचार नीति का अनुसरण करता है, जो गतिशील है और जिसका लक्ष्य समाज के भीतर सभी समूहों तक पहुंचने के लिए निर्धारित वार्ताकारों के साथ व्यापक और विविध सामाजिक स्पेक्ट्रम है। संदेश प्रत्येक समूह के अनुरूप हैं क्योंकि पीएसी का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के जागरूकता संदेशों को समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संचार के प्रसार से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने में मदद मिली।

X.8 वर्ष 2022-23 के दौरान, संचार विभाग (डीओसी) ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न चैनलों, जैसे टेलीविजन (टीवी), प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आउट-ऑफ-होम (ओओएच), शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम (एसएमएस) और सिनेमा का उपयोग करके आवश्यकता आधारित संचार का प्रसार किया। आवश्यकता आधारित अभियान का विवरण सारणी X.1 में दिया गया है।

X.9 इन विषयगत अभियानों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनता को जानकारी प्रसारित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) और फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) विश्व कप जैसे उच्च प्रभाव/विशिष्ट कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। टियर III और IV शहरों

सारणी X.1: अनुकूलित अभियान: 2022-23

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	जून 2022
2. बेदावा जमाराशि	जुलाई - अगस्त 2022
3. टोकनाइजेशन	जुलाई - अक्टूबर 2022
4. सिक्कों पर अभियान	अगस्त - सितंबर 2022
5. विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर अभियान	सितंबर – अक्टूबर 2022
6. आरबी - आईओएस पर पुन: अभियान	सितंबर - अक्टूबर 2022
7. सीईपीडी एसएमएस अभियान	नवंबर 2022
8. यूपीआई/क्यूआर कोड का उपयोग कर धोखाधड़ी	नवंबर 2022
9. डिजिटल/बैंकिंग लेन-देन में सीमित देयता	नवंबर - दिसंबर 2022
10. सकारात्मक वेतन प्रणाली	नवंबर - दिसंबर 2022
11. नोटों का विनिमय	नवंबर - दिसंबर 2022
12. वित्तीय साक्षरता सप्ताह	फरवरी 2023
13. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह	मार्च 2023

आरबी-आईओएस : रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना।
सीईपीडी : उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग।
यूपीआई/क्यूआर : एकीकृत भुगतान इंटरफेस/त्वरित प्रतिक्रिया।
स्रोत: आरबीआई।

में अधिक पहुंच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, *अर्थात्* आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अभियान भी जारी किए गए।

X.10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग हर हफ्ते आकर्षक पोस्टर, लघु वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, एनीमेशन क्लिप, पोल, ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रारूप (जीआईएफ) और कथाओं के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता संदेश भी जारी किए जाते हैं। बेहतर स्मरण के लिए, सभी पीएसी में शुभंकर 'मनी कुमार' का उपयोग किया जाता है । जनवरी 2023 से शुभंकर के रूप में मिस मनी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये अभियान, सभी मास मीडिया को शामिल करने वाले 360 डिग्री अभियान के पूरक हैं। आरबीआई की यह संचार पहल सभी मामलों में अद्वितीय है- जिसमें जनता के बड़े भाग पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसकी जड़े देश की संस्कृति में गहराई में हैं, जिसमें अभी भी समय और विकसित प्रौद्योगिकी का तालमेल है (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंक संचार में सोशल मीडिया का उपयोग

आज की तेजी से बदलती और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित दुनिया में, सोशल मीडिया केंद्रीय बैंकिंग संचार में एक आवश्यक उपकरण है। कई केंद्रीय बैंकों ने अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्म पर अपने स्वयं के सोशल मीडिया चैनल स्थापित किए हैं। प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म की अपनी कार्यप्रणाली और लक्षित दर्शकों के साथ, केंद्रीय बैंक अपने संदेशों को विभिन्न सोशल मीडिया के अनुरूप बनाने में अधिक सुस्पष्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया ने केंद्रीय बैंकों को पहले से अगम्य दर्शकों जैसे कि वे लोग जो पारंपरिक मीडिया पर समाचारों का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। अधिक मौलिक रूप से कहे तो, सोशल मीडिया ने केंद्रीय बैंकों को जनता से सीधे बात करने में सक्षम बनाया है।

रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद करने के सचेत प्रयास किए हैं। रिज़र्व बैंक की इंस्टाग्राम, फेसबुक, पब्लिक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी है। रिज़र्व बैंक के दो ट्विटर हैंडल (@RBI और @RBIsays), दो फेसबुक अकाउंट (@RBIsays और @therbimuseum), एक यूट्यूब चैनल (Reserve Bank of India) और एक इंस्टाग्राम अकाउंट (reservebankofindia) है। आरबीआई ने 4 जनवरी, 2023 को 'पब्लिक ऐप (@RBIsays) पर भी एक खाता शुरू किया है। इस ऐप का उपयोग करके, रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता संदेशों और वीडियो को आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में लक्षित और साझा किया जा सकता है, वह भी स्थानीय भाषाओं में, ताकि अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच व्यापक प्रसार के लिए इन प्लेटफार्मों पर जानकारी निरंतर और अनुरूपता से अपडेट की जाती है। सोशल मीडिया का उपयोग वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, जन जागरूकता और रिज़र्व बैंक के नीतिगत निर्णयों के बारे में जनता में सूचना प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी किया जाता है (सारणी 1)।

रिज़र्व बैंक अपने सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) के माध्यम से नियमित आधार पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी करता है और इन प्लेटफार्मों पर पोस्ट जारी करता है। प्रतिक्रिया सीमित तरीके से सीधे संदेशों के माध्यम से सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जाती है। रिज़र्व बैंक के नाम से फर्जी पृष्ठों की नियमित रूप से पहचान की जाती है और पृष्ठों को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा, विभाग नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट, पहुंच, प्रमुख संदेशों और शीर्ष हैशटैग का विश्लेषण करता है।

सारणी 1: सोशल मीडिया उपस्थिति*

प्लेटफार्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या
1	2	3	4
ट्विटर	i.@RBI	जनवरी 2012	19.7 लाख
	ii.@RBIsays	अगस्त 2019	1.95 लाख
यूट्यूब	रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया	अगस्त 2013	1.71 लाख
फेसबूक	i.@RBIsays	अगस्त 2019	7,800
	ii.@therbimuseum	फरवरी 2020	1,460
इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	2.1 लाख
जनता	@RBIsays	जनवरी 2023	29,000

*: 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार।
स्रोत: आरबीआई।

उदाहरण 1: सुश्री मनी और मनी कुमार

स्रोत: आरबीआई।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.11 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इंटरैक्टिव अभियानों के लिए चित्र, एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स जोड़कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक जागरूकता संदेशों की परत-दर-परत शुरुआत (पैराग्राफ X.10);
- रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को बेहतर सूचना संरचना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.12] के साथ नया रूप देना;

- इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम जनता के साथ अधिक जुड़ाव और सक्रिय सोशल मीडिया श्रवण (*उत्कर्ष*) के माध्यम से दो-तरफा संचार प्रयासों को बढ़ाना [पैराग्राफ X.13];
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर लक्षित मीडिया निगरानी (पैराग्राफ X.13);
- रिज़र्व बैंक की आंतरिक और बाह्य संचार सामग्री को सरल बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में लिखित संचार में शैली और उपयोग पर पुनर्विचार करना (पैराग्राफ X.14); और
- रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों की प्रभावोत्पादकता का आकलन करना (पैराग्राफ X.15)।

कार्यान्वयन की स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट का नवीकरण

X.12 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के पुनः डिज़ाइन और विकास के लिए कार्य प्रगति पर है। इसका उद्देश्य अपने सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और समय पर सूचना का प्रसार सुनिश्चित करते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। नवीकृत वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन 2023 में सक्रिय हो जाएगा।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी)

X.13 रिज़र्व बैंक की फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर मौजूदगी है। विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच व्यापक प्रसार के लिए इन प्लेटफार्मों पर जानकारी लगातार और अनुरूप तरीके से अद्यतन की जाती है। एसएमसीसी नियमित आधार पर रिज़र्व बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी करता है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी करता है।

लिखित संचार में शैली और उपयोग पर पुनर्विचार

X.14 केंद्रीय बैंक से संचार बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसका लक्ष्य देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की बेहतर ढंग से सूचना प्रदान करना, विनियमन करना, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना है। रूप और सामग्री किसी भी संचार के अभिन्न अंग हैं। विभाग ने रिज़र्व बैंक के संचार की 'शैली और उपयोग' पर फिर से विचार करने का कार्य शुरू कर दिया है और यह प्रगति पर है।

रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव आकलन

X.15 रिज़र्व बैंक ने जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया है। समग्र सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर है। आकलन मई 2023 में पूरा होने की संभावना है।

अन्य पहल

'दि आरबीआई म्यूजियम' का दूसरा चरण

X.16 रिज़र्व बैंक ने आरबीआई, कोलकाता में एक अत्याधुनिक 'दि आरबीआई म्यूजियम' की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन 11 मार्च 2019 को किया गया था। संग्रहालय बहुत ही रोचक एवं चर्चापरक तरीके में पैसे की अवधारणा, अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका और इसमें जनता की भूमिका, सदियों से पैसे के विभिन्न रूप कैसे विकसित हुए हैं, कैसे और क्यों सवर्ण अभी भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसकी सुखद और संवादापरक तरीके से व्याख्या करता है। 31 मार्च 2023 के अंत तक, संग्रहालय में स्थापना के बाद से 17,300 से अधिक आगंतुक आए थे। आरबीआई संग्रहालय के दूसरे चरण से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक पर 'द आरबीआई म्यूजियम' पेज का भी उपयोग करता है।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.17 गवर्नर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद, द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हैं। घोषणा के बाद, गवर्नर और उप गवर्नर मौद्रिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह की छह चर्चाएं आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला

X.18 रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय मीडिया के साथ नियमित कार्यशालाएं और चर्चाएं आयोजित करता है। इस तरह की कार्यशालाओं का उद्देश्य मीडियाकर्मियों को केंद्रीय बैंक के कामकाज की बेहतर और अधिक सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्रदान करने और रिज़र्व बैंक की नीतियों के पीछे की नवीनतम घटनाओं, अवधारणाओं और तर्क के बारे में जागरूक होने में सक्षम बनाना है। गुवाहाटी, अहमदाबाद और कोच्चि में वर्ष के दौरान ऐसी तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

अनौपचारिक मीडिया इंटरैक्शन

X.19 मौद्रिक नीति प्रेस सम्मेलनों के अलावा, रिज़र्व बैंक अनौपचारिक रूप से मीडिया के साथ चर्चाएं आयोजित करता है जब भी इस तरह की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान इस तरह की 30 चर्चाएं आयोजित की गईं।

आरबीआई की वेबसाइट

X.20 2022-23 के दौरान, विभाग ने 1,952 प्रेस प्रकाशनी, 200 अधिसूचनाएं, 22 परिपत्र, छह मास्टर निर्देश जारी किए हैं और शीर्ष प्रबंधन के 18 साक्षात्कार और 36 भाषण, छह आरबीआई रिपोर्ट, 10 वर्किंग पेपर, 1,375 निविदाएं और 32 भर्ती से संबंधित विज्ञापन अपलोड किए हैं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.21 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और सुदृढ़ किया जाएगा, और निम्नलिखित दिशा में प्रयास किए जाएंगे:

- आरबीआई के जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन को पूरा किया जाना *(उत्कर्ष* 2.0*);*
- सभी हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट का शुभारंभ *(उत्कर्ष* 2.0*);* और
- कोलकाता में 'आरबीआई संग्रहालय' के दूसरे चरण का पूरा करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.22 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ब्रिक्स[2] और सार्क फाइनेंस जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त किया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता संभाली है। जी-20 की अध्यक्षता के तहत, रिज़र्व बैंक वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) के समन्वय से वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और संबंधित वितरण पर कार्य करेगा। भारत ने वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता संभाली और रिज़र्व बैंक वित्त ट्रैक के तहत वितरण पर कार्य करेगा। रिज़र्व बैंक दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र की अध्यक्षता

[2] ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

ग्रहण करेगा और 59वीं एसईएसीईएन गवर्नर्स सम्मेलन/उच्च स्तरीय संगोष्ठी और एसईएसीईएन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 43वीं बैठक की मेजबानी करेगा।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.23 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी) के तहत मुद्दों सहित बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहभागिता बढ़ाना (पैराग्राफ X.24-X.26 और X.34);
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी-20 वित्त ट्रैक कार्ययोजना के लिए सलाहकार समूह में सहभागिता जिससे कि प्राथमिकताओं पर विचार किया जा सके, परिणामों/वितरणों पर सुझाव दिया जा सके और जी20 की वर्ष 2023 की भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त ट्रैक कार्ययोजना पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। (बॉक्स X.2);
- सहभागिता के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के सहयोग को मजबूत करना (पैराग्राफ X.27);
- औपचारिक सहमति ज्ञापन (एमओयू) या अन्यथा के माध्यम से सार्क और अन्य देशों के लिए एक्सपोजर दौरों और क्षमता निर्माण समर्थन में वृद्धि (पैराग्राफ X.28-X.32); और
- भारत 1 दिसंबर, 2022 को जी 20 की अध्यक्षता संभालेगा और भारत सरकार के सहयोग से कई उच्च स्तरीय और कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की जाएंगी (पैराग्राफ X.33-X.37)।

कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ

X.24 विभाग ने अप्रैल और अक्तूबर 2022 में आयोजित फंड-बैंक बैठकों के दौरान प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास; वैश्विक नीति एजेंडा; और आईएमएफ कोटा और अभिशासन सुधारों पर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) के विचार-विमर्श के लिए इनपुट प्रदान किए।

X.25 विभाग ने 14-27 सितंबर, 2022 के दौरान आयोजित आईएमएफ अनुच्छेद IV मिशन को पूरा करने में मदद की। भारत 2022 अनुच्छेद IV परामर्श स्टाफ रिपोर्ट 23 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित हुई थी। विभाग ने आईएमएफ के विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया जैसे विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईएईआर), समष्टि विवेकपूर्ण नीतिगत सर्वेक्षण, जलवायु मुद्दों और नीतियों पर सर्वेक्षण, और केंद्रीय बैंकों की संधारणीयता पहल पर सर्वेक्षण। विभाग ने देश के प्राधिकरणों के लिए अभिशासन पर आईएमएफ के सर्वेक्षण में भी भाग लिया।

X.26 विभाग ने रिज़र्व बैंक के रुख को मजबूत किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर एमओएफ, भारत सरकार को जानकारी प्रदान की। इसने विश्व बैंक के भारत विकास अद्यतन 2022 के लिए भी जानकारी प्रदान की और कोड पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सलाहकार कार्यदल[3] (एटीएफसी) की बैठकों में भाग लिया।

बिक्स, सार्क, एससीओ और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए) की तकनीकी टीम ने सीआरए संधि में संशोधन के लिए प्रमुख सिफारिशों, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया, जो वैकल्पिक भुगतान मुद्राओं के उपयोग सहित सीआरए तंत्र में अधिक लचीलापन लाएगा, और इस प्रकार क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था (आरएफए) को मजबूत करेगा। ब्रिक्स अनुसंधान

[3] पूंजी संचलन और वर्तमान अदृश्य संचालन के उदारीकरण के ओईसीडी कोड।

समूह ने ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2022 निकाला, जिसमें हाल के नीतिगत उपायों को प्रतिबिंबित करते हुए ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को कवर किया गया और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली (एसएएमआई) को जारी रखा गया। ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और मार्गस्थ वित्त (ट्रांजिट फाइनेंस) पर दो स्टॉक पड़ताल सर्वेक्षण किए, और सूचना सुरक्षा और भुगतान प्रणालियों पर संवाद और चर्चा जारी रखी।

X.28 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अनुमोदन से मुद्रा अदला-बदली (स्वैप) व्यवस्था 2019-22 पर सार्क ढांचे की वैधता 13 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान (आरएमएबी) के साथ और दिसंबर 2022 में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। रिज़र्व बैंक ने 2022-23 के दौरान तीन सार्क केंद्रीय बैंकों को कुल मिलाकर 0.9 बिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली सहायता भी दी है।

X.29 सार्क क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों को मजबूत करते हुए, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के दस अधिकारियों को छह सप्ताह के लिए डेटा एनालिटिक्स पर रिज़र्व बैंक के साथ अपनी तरह का पहला इंटर्नशिप अवसर प्रदान किया गया था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) और आरएमएबी को तकनीकी सहायता प्रदान की। अगस्त 2022 में सार्क केंद्रीय बैंकों के लिए 'मुद्रास्फीति की गतिशीलता और दक्षिण एशिया में इसका नियंत्रण' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

X.30 एमएमए द्वारा आयोजित सार्क फाइनेंस डेटाबेस (एसएफडीबी) संगोष्ठी में 'केंद्रीय बैंकों द्वारा उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग: अनुभव और आगे की योजनाएं' विषय पर एक देशीय पत्र (कंट्री पेपर) प्रस्तुत किया गया था। एसएफडीबी संगोष्ठी के साथ, रिज़र्व बैंक ने एसएफडीबी कार्य समूह की बैठक आयोजित की और सार्क केंद्रीय बैंकों को डेटाबेस में प्रस्तावित सुधार के बारे में अद्यतन किया ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और गतिशील बनाया जा सके।

X.31 रिज़र्व बैंक ने 2023 के लिए एससीओ अध्यक्ष के तहत केंद्रीय बैंक के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में एससीओ देशों में डिजिटल वित्त समावेशन पर रिपोर्ट' तैयार की। भारत ने 3 मार्च, 2023 को एससीओ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की।

X.32 बैंक ऑफ जापान और रिज़र्व बैंक के बीच वरिष्ठ स्तरीय वार्ता 16 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों में व्यापक आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने, डिजिटल उधार नियमों और भारतीय अध्यक्षता के तहत चुनिंदा जी 20 मुद्दों के विषयों को कवर किया गया।

जी20 और इसके कार्य समूह

X.33 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत, भारत ने विभिन्न कार्यसमूहों की बैठकों के अलावा, जी 20 ट्रोइका सदस्य के रूप में जी 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठकों और वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की बैठकों में भाग लिया।

X.34 2022 में, जी20 इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत, विभाग ने जी20 आईएफए डब्ल्यूजी की बैठकों में भाग लिया, और पूंजी प्रवाह से संबंधित मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए, और पूंजी प्रवाह के उदारीकरण और प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के संस्थागत दृष्टिकोण की समीक्षा, एक एकीकृत नीति ढांचे पर आईएमएफ का काम; बीआईएस मैक्रो वित्तीय स्थिरता नीति ढांचे पर काम; वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) की पर्याप्तता; और आईएमएफ के विशेष

आहरण अधिकारों (एसडीआर) की चैनलिंग पर चर्चा में शामिल हुए।

X.35 भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी 20 की अध्यक्षता संभाली। भारत के जी20 अध्यक्षता का विषय - *'वसुधैव कुटुम्बकम'* या 'एक पृथ्वी · एक परिवार · 'एक भविष्य' - मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव - और ग्रह पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड में उनके अंतर-जुड़ाव सहित सभी के जीवन के मूल्य को मानता है। वित्त ट्रैक के भीतर, भारत की प्राथमिकताओं में *अन्य बातों के साथ-साथ*, डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उभरने वाले अवसर और जोखिम, जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन, विकास और बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना शामिल है (बॉक्स X.2)।

बॉक्स X.2
जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2023 के तहत वित्त ट्रैक (एफटी) प्राथमिकताएं

भारत ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के बीच जी-20 की अध्यक्षता संभाली जो वैश्विक विकास की गति की कमजोरी, कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित मौद्रिक नीति में सख्ती और उससे जुड़े प्रभावों, भू-राजनीतिक तनाव, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन और महामारी के सुस्त प्रभावों जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बहुसंकट का सामना कर रहा है।

जी-20 के भीतर, एफटी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, उनके प्रतिनिधियों और विभिन्न कार्यकारी समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। एफटी द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक आर्थिक जोखिमों की निगरानी; अधिक स्थिर और लचीले वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार; अंतरराष्ट्रीय कराधान; गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का वित्तपोषण; स्थायी वित्त; वित्तीय समावेशन; वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वित्तपोषण और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में निवेश हैं। इन विविध मुद्दों से निपटने के लिए, जी-20 ने समय के साथ कार्यकारी समूहों की स्थापना की है, अर्थात् फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) और संपोषणीय वित्त कार्यदल (एसएफडब्ल्यूजी), और संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यदल (जेएफएचटीएफ)। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों को क्रमशः एफएसबी और ओईसीडी की सहायता से डिप्टी स्तर पर सीधे निपटाया जाता है, और वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने जी-20 एफटी के लिए प्राथमिकताओं और वितरण को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समूह की बैठकों में योगदान दिया। भारत की अध्यक्षता के तहत, प्रमुख एफटी प्राथमिकताओं में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना और स्थायी पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करना शामिल है। यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक परिणामों का आकलन और मैक्रो पॉलिसी सेटिंग के लिए परिणामी प्रभावों का आकलन, कल के समावेशी, लचीले और स्थायी शहरों का वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन और संक्रमण मार्गों के व्यापक आर्थिक प्रभाव का देश-संचालित मूल्यांकन विकसित करने के साथ केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और उनके समष्टि-वित्तीय प्रभावों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना एक प्राथमिकता है। संपोषणीय वित्त के संबंध में प्राथमिकताओं में जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र पर काम करना, निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए वित्त को सक्षम करना और सतत विकास की दिशा में वित्तपोषण के लिए पारितंत्र का क्षमता निर्माण शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के अंतर्गत, भारत ने तकनीकी विकास द्वारा पेश किए गए जोखिमों और अवसरों दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव दिया है। क्रिप्टो बाजारों में आवर्ती उथल-पुथल, कुछ स्थिर सिक्कों का अन-अधिकीलन (डी-पेग्गिंग) और व्यापक क्रिप्टो बाजारों के बाजार मूल्य में परिणामी गिरावट ने इन आशंकाओं को प्रबल किया है कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए एक भौतिक खतरा हैं। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और वित्तीय अखंडता की चिंताओं से परे जी 20 क्रिप्टो आस्ति परिभाषा का विस्तार करना है ताकि क्रिप्टो आस्तियों के मैक्रो-वित्तीय और क्रॉस-सेक्टोरल इंप्लीकेशन्स और जोखिमों को प्राप्त किया जा सके। अध्यक्ष पद क्रिप्टो-आस्तियों, स्थिर सिक्कों और डीईएफआई के वैश्विक विनियमन के लिए एक ढांचा बनाकर संयुक्त रूप से जी 20 में एक समन्वित और व्यापक नीति दृष्टिकोण को आकार देने का इरादा रखता है। तेजी से बढ़ती डिजिटल वित्तीय सेवाएं और तीसरे पक्ष की सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता वित्तीय प्रणाली को परिचालन, तरलता और एकाग्रता जोखिमों के लिए उजागर करती है। इसकी अध्यक्षता में, भारत अन्य बातों के साथ-साथ, बिगटेक और फिनटेक से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना चाहेगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल हो जाती है, साइबर जोखिम वित्तीय प्रणाली के लिए एक खतरा है, क्योंकि शृंखला में कहीं भी आउटेज पूरे वित्तीय प्रणाली पर असर करने वाले व्यापक प्रभाव पैदा कर सकता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान, वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को

(जारी..)

मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग हेतु एक रिपोर्टिंग ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निरंतर विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक प्रवासियों की विप्रेषण लागत को 3 प्रतिशत से कम करने के उद्देश्य से; और भुगतान की उत्पत्ति और निपटान के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए, भारत की अध्यक्षता धन के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय तेजी से भुगतान प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता पर राष्ट्रीय अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय पहलों पर जानकारी साझा करने को प्राथमिकता देगी। भारत की अध्यक्षता एक डिजिटल वित्तीय परितंत्र विकसित करने और आर्थिक विकास में सहायता के लिए रचनात्मक और कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशों की मदद से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की दिशा में भी काम करेगी। इसके अलावा, भारत जी 20 प्रेसीडेंसी के तहत, जीपीएफआई एक नई वित्तीय समावेशन कार्य योजना 2023 तैयार कर उसे अपनाएगा जो पब्लिक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक-आधारित वित्तीय परितंत्र और पहल की स्थापना के लिए कार्यान्वयन ढांचे को विकसित करके एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रक्षेपवक्र निर्धारित करेगा। इसके अलावा, 6-7 मार्च, 2023 के दौरान हैदराबाद में वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में संपन्न दूसरी जी 20 वैश्विक भागीदारी बैठक में, भारत और इटली को पूरी सदस्यता के समर्थन के साथ नए जीपीएफआई सह-अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था।

X.36 दिसंबर 2022 में भारत के जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से विभाग कई डोमेन विभागों के साथ समन्वय में आरबीआई से संबंधित कई जी-20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं पर प्रायोगिक आधार पर काम कर रहा है। आईएफए डब्ल्यूजी के अंतर्गत, विभाग निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर कार्य कर रहा है *अर्थात्* (i) सीबीडीसी के समष्टि-वित्तीय निहितार्थों का आकलन; और (ii) सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलापन को सुदृढ़ करना। वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों में, बैंक (i) निधियों के निर्बाध सीमा-पार प्रवाह के लिए राष्ट्रीय तीव्र भुगतान प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता पर राष्ट्रीय अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय पहलों पर सूचना साझा करने; (ii) बिगटेक और फिनटेक से संबंधित अन्य बातों के साथ-साथ तृतीय-पक्ष जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना; और (iii) वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार करना जैसे मुद्दों पर अग्रणी कार्य कर रहा है।

X.37 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की पहली बैठक भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी, जहां अध्यक्षीय प्राथमिकताओं को सदस्यता और आईओ के व्यापक समर्थन के साथ पूरा किया गया। जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की पहली बैठक और एफसीबीडी की दूसरी बैठक फरवरी 2023 में आयोजित की गई थी। जी-20 एफएमसीबीजी के चेयर समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट में वैश्विक ऋण संकट, एमडीबी सुधार, जलवायु वित्त, क्रिप्टो पर वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, कल के वित्तपोषण शहरों और कराधान जैसे विषयों पर भारत की अध्यक्षता में 2023 में जी-20 की प्राथमिकताओं और भविष्य के कार्यों को रेखांकित किया गया है। रिज़र्व बैंक ने पहली एफसीबीडी बैठक और दूसरी एफसीबीडी बैठक से इतर 'हरित वित्तपोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका' और 'सीमा-पार भुगतान: राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों की भूमिका पर परिप्रेक्ष्य' विषय पर केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरबीआई ने जनवरी 2023 में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं: अवसर और चुनौतियां' पर एक पैनल चर्चा और मार्च 2023 में 'एक खंडित दुनिया में जीएफएसएन को मजबूत करना' पर जी20 संगोष्ठी का भी आयोजन किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक जी20 फाइनेंस ट्रैक बैठकों से पहले कई घरेलू आउटरीच और सार्वजनिक भागीदारी (जन भागीदारी) कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

अन्य पहल

बीआईएस के साथ सहभागिता

X.38 विभाग ने विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की जिसने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की बैठकों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) की बैठकों में चर्चा किए

गए मुद्दों पर रिज़र्व बैंक के रुख को आकार प्रदान किया। बीआईएस संवाद और विश्लेषण के लिए एक मंच है, आर्थिक और वित्तीय विकास पर चर्चा करता है और मुख्य नीतिगत मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कीमतों और मजदूरी से संबंधित गतिविधियां चर्चा के प्रमुख विषय थे। बीआईएस की बैठकों में मौद्रिक सख्ती स्पिलओवर, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और विश्व व्यापार, वित्तीय स्थिरता जोखिम और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समष्टि-वित्तीय लिंकेज, विकेंद्रीकृत वित्त, जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय बैंक लाभप्रदता से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है। वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीएफएस की बैठकों में उतार-चढ़ाव वाले अस्थिर वस्तु बाजारों और वित्तीय स्थिरता पर मौद्रिक सख्ती के परिणामों, संपत्ति बाजारों में गिरावट से संभावित जोखिम, सीमापार स्पिलओवर में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) की भूमिका, बढ़ती ब्याज दरों के प्रति एनबीएफसी की संवेदनशीलता और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया।

X.39 विभाग ने भविष्य के सीजीएफएस कार्य कार्यक्रम और सीजीएफएस को मजबूत करने के तरीकों पर सीजीएफएस सर्वेक्षणों में योगदान दिया। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस वार्षिक उभरते बाजार डिप्टी गवर्नर की बैठक में रिज़र्व बैंक की भागीदारी, मुद्रास्फीति पर बीआईएस कार्य समूह, बाहरी वित्तीय स्थितियों और एशिया-प्रशांत में समष्टि-वित्तीय स्थिरता ढांचे, आवास से संबंधित जोखिमों को कम करने पर सीजीएफएस अध्ययन समूह और जलवायु जोखिमों और परिसंपत्ति की कीमतों पर सीजीएफएस कार्यशाला का समन्वय किया। विभाग द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जैसे सामयिक मुद्दों पर बीआईएस द्वारा वेबिनार भी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस बोर्ड और इसकी प्रशासनिक समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता और इनपुट प्रदान किए।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहल

X.40 विभाग ने व्यापक मुद्दों पर एफएसबी में भारत का रुख तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों का आकलन और निगरानी; गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफसी) क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाना; क्रिप्टो-आस्तियां और अन्य डिजिटल नवाचार; सीमा पार भुगतान में वृद्धि; साइबर और परिचालनात्मक लचीलापन; और जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों का समाधान करना शामिल था।

X.41 भारत एफएसबी के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह एशिया (आरसीजी-एशिया) का सह-अध्यक्ष होने के नाते, विभाग इसकी दो बैठकों में शामिल था। इन बैठकों में अस्थिर कमोडिटी कीमतों, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों से क्षेत्र में उत्पन्न वित्तीय स्थिरता के लिए सदस्यों के दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों का समाधान करने पर क्षेत्र के भीतर की जा रही प्रगति; और सीमापार भुगतान पर एफएसबी का चल रहा काम और सीमापार भुगतान पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

X.42 विभाग ने एफएसबी और वित्तीय प्रणाली के हरित वित्तपोषण नेटवर्क (नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम) (एनजीएफएस) द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों में योगदान दिया। विभाग ने एफएसबी की वार्षिक निगरानी कार्रवाई में भी योगदान दिया, जो एनबीएफसी क्षेत्र में वैश्विक रुझानों का आकलन करती है। इस कार्रवाई के तहत विभाग ने 'गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर एफएसबी की 2022 वैश्विक निगरानी रिपोर्ट' के लिए आंकड़े/इनपुट उपलब्ध कराए।

अन्य गतिविधियाँ

X.43 रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी), एसईएसीईएन केंद्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ),

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), तीस सदस्यीय समूह (जी30) और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास (जी-24) पर चौबीस सदस्यीय अंतर-सरकारी समूह जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी।

X.44 विभाग ने एसएआरटीटीएसी, आईएमएफ और आईएमएफ के अन्य क्षमता विकास केंद्रों द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में रिज़र्व बैंक की भागीदारी का समन्वय किया। वर्ष के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों के साथ समन्वय में एसईएसीईएन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। विभाग ने वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के लिए आईएमएफ के एक तकनीकी सहायता (टीए) मिशन की व्यवस्था की ताकि इसकी विश्लेषणात्मक क्षमता और सॉल्वेंसी जोखिम विश्लेषण, चलनिधि जोखिम विश्लेषण और भारत में बैंकों के तुलनपत्र की संबद्धता के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडलों की समीक्षा की जा सके।

X.45 विभाग ने दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच आपसी सहयोग में सुधार के लिए जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के अवसर पर 16 जुलाई, 2022 को बाली, इंडोनेशिया में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति ज्ञापन के साथ, आरबीआई और बीआई ने दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहरा करने और भुगतान प्रणालियों, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल-सीएफटी) के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे सहित केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस सहमति ज्ञापन को नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के माध्यम से लागू किया जाएगा।

X.46 यह विभाग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं/ बैठकों के समन्वय और व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर इनपुट तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक में नोडल बिंदु है। इस संदर्भ में, विभाग ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों, वित्तीय विनियमन, व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक नीतियों और अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों को कवर करने वाले विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.47 वर्ष के दौरान, विभाग रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को तेज करेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- जी 20 प्रेसीडेंसी फाइनेंस ट्रैक (*उत्कर्ष* 2.0);
- आईएमएफ-डब्ल्यूबी संयुक्त पंचवर्षीय निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (*उत्कर्ष* 2.0); और
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार की सहमति से, 2023-26 (*उत्कर्ष* 2.0) के लिए सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा तैयार करेगा/

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.48 सरकार और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखों का रखरखाव करने और रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा, बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों को संभालता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.49 विभाग ने 2022-23 के लिए उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *ई-कुबेर* और लोक निधि प्रबंधन प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से केंद्रीय सिविल मंत्रालयों द्वारा भुगतान (गैर-पेंशन) को बढ़ाना, जिसमें

अंतर-सरकारी समायोजन सलाह (पैराग्राफ X.50) शामिल है;

- उन राज्य सरकारों के ई-भुगतान लेनदेनों (गैर-पेंशन) को बढ़ाना जो पहले से ही *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत हैं (पैराग्राफ X.51);
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष बचे राज्य सरकारों को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत करना (पैराग्राफ X.51); और
- प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण (पैराग्राफ X.52);
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आइसगेट पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए एजेंसी बैंकों को जोड़ना [पैराग्राफ X.53]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.50 *ई-कुबेर* और लोक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के बीच एकीकरण का उपयोग केंद्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने बड़े भुगतान के लिए किया जा रहा है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) ढांचे के माध्यम से केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के भुगतान के लिए इस एकीकरण को बढ़ाया गया है। टीएसए ढांचे को कुछ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और वैधानिक निकायों के लिए भी विस्तारित किया गया है। वर्तमान में, पीएफएमएस इलेक्ट्रॉनिक अंतर-सरकारी समायोजन सूचना के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकरण का भी उपयोग कर रहा है, और विभाग इसे एक उन्नत संस्करण में स्थानांतरित करने के लिए कार्य कर रहा है।

X.51 पूर्वोत्तर क्षेत्र की तीन राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों को ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया है। इनमें से कई राज्य सरकारें अपने अधिकांश ई-भुगतान लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर का उपयोग कर रही हैं, जो सरकारों के लिए ' समय पर भुगतान (जस्ट-इन-टाइम)' भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है।

X.52 वर्ष के दौरान, चार और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया, जिससे एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत राज्य सरकारों की कुल संख्या सात हो गई।

X.53 सीबीआईसी की भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) प्रणाली को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 1 जुलाई, 2019 से अप्रत्यक्ष करों [वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा], जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, के संग्रह के लिए लागू किया गया। बाद में 1 जुलाई, 2020 से सीबीआईसी के आईसईगेट को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करके सीमा शुल्क के संग्रह को भी सक्षम किया गया। आईसीईगेट पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क प्राप्तियों और अन्य संबंधित अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए एक अग्रिम या प्री-पेड भुगतान वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एजेंसी बैंकों ने प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए ओएलटीएएस प्लेटफॉर्म से टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर भी स्थानांतरित कर दिया है (बॉक्स X.3)।

अन्य पहल

ई-कुबेर के माध्यम से संसाधित कुछ सरकारी लेनदेन की स्थिति पर डैशबोर्ड सुविधा का विकास।

X.54 डैशबोर्ड सुविधा विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है। रिज़र्व बैंक इस कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए प्रायोगिक आधार पर सरकारों को ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया में है।

बॉक्स X.3
करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए पहल

करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी के लिए भारत सरकार के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने हाल के दिनों में कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों जैसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और राज्य सरकारों की प्रणालियों के साथ ई-कुबेर (रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान) का एकीकरण है ताकि सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जा सके। यह न केवल करदाताओं के लिए बल्कि सरकार के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि लेनदेन का सामंजस्य तेज और कार्यक्षम है, जिससे सरकार में कुशल नकदी प्रबंधन होता है। 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहल, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा, इस प्रकार हैं:

टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रह

ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के संग्रह की मौजूदा प्रक्रिया को कर सूचना नेटवर्क (टिन) 2.0 में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे आयकर विभाग और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय के तहत पीएफएमएस के एक एप्लिकेशन 'प्रकल्प' *(प्रत्यक्ष कर लेखन प्रणाली)* के माध्यम से टिन 2.0 के तहत सरकारी लेनदेन के लेखा-जोखा की सुविधा प्रदान की जा रही है। रिज़र्व बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एक संग्रहण बैंक के साथ-साथ ई-कुबेर के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के लेखांकन और निपटान के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहा है, जिसे एजेंसी बैंकों, टिन और प्रकल्प की प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, एजेंसी बैंक जो अब तक ओएलटीएएस प्लेटफॉर्म के तहत प्रत्यक्ष करों का संग्रह कर रहे थे, वे टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए लाइव हो गए हैं और टीआईएन 2.0 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कर संग्रह की सूचना इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को टी + 1 आधार पर दे रहे हैं, जिससे त्वरित और कुशल सामंजस्य संभव हो सके। ओएलटीएएस के तहत करदाता केवल एजेंसी बैंकों के माध्यम से अपने करों का भुगतान कर सकते थे। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-एजेंसी बैंकों में खाते रखने वाले करदाता टिन 2.0 के तहत करों का भुगतान करने में सक्षम हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष करों के संग्रह को भी 1 अगस्त, 2022 से लाइव कर दिया गया है। यह करदाताओं को भारत के किसी भी बैंक, जो 24 x 7 आधार पर, एनईएफटी/आरटीजीएस भागीदार बैंक[4] हैं, में उनके खातों से प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में आसानी प्रदान करता है, उसी दिन सरकार के खाते में कर राशि जमा करने में सक्षम बनाता है।

सीमा शुल्क - आइसगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल)

1 जुलाई, 2019 से, रिज़र्व बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से आईसीईगेट [भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे] प्राप्तियों के लिए संग्रहणकर्ता बैंक है। ईसीएल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें सीबीआईसी द्वारा अधिकृत एजेंसी बैंकों के माध्यम से और एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे रिज़र्व बैंक द्वारा आईसीईगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। ईसीएल ढांचे में, ईसीएल एक अग्रिम या प्री-पेड भुगतान वॉलेट की तरह काम करेगा, जिसमें करदाता उनके द्वारा तय की गई राशि का पूर्व-भुगतान कर सकते हैं, जिसे उनके कर बही खाते में जमा किया जाएगा, लेकिन इस प्री-पेड राशि से संबंधित कर शीर्षों (जैसे सीमा शुल्क, उपकर, उत्पाद शुल्क, आदि) को करों का वास्तविक आबंटन करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले वास्तविक कर के अनुसार बाद में किया जाएगा। जीएसटी की तरह, रिज़र्व बैंक प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एक संग्रहण बैंक है और साथ ही ईसीएल के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए एक समग्र बैंक है।

ईसीएल फ्रेमवर्क करदाताओं को सुविधा प्रदान करता है क्योंकि वे न केवल एजेंसी बैंकों के माध्यम से बल्कि भारत के किसी भी वाणिज्यिक बैंक में अपने खातों से सीधे रिज़र्व बैंक को आईसीईगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर भुगतान कर सकते हैं, जो 24x7 आधार पर एनईएफटी / आरटीजीएस भागीदार बैंक है, जिससे उसी दिन सरकार को कर राशि जमा की जा सकती। ईसीएल को 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन

X.55 भारत सरकार (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) के 9 मार्च, 2022 के ज्ञापन के अनुसार, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के समन्वय से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत धन के प्रवाह के लिए एक संशोधित प्रक्रिया को वर्ष के दौरान लागू किया गया था। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है कि

[4] आज की तारीख में 200 से अधिक ऐसे बैंक, जिनमें भारत में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं।

500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना लागू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में, टीएसए मॉडल के माध्यम से ऐसी योजनाओं को लागू करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन योजनाओं की धनराशि समय पर जारी की जाए।

5. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

X.56 वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती और डी-डॉलराइजेशन और आरक्षित आस्तियों के विविधीकरण के लिए उभरते हालिया वैश्विक रुझान ने केंद्रीय बैंकों की आरक्षित निधियों के प्रबंधन की पद्धतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरों में समन्वित वृद्धि हुई है। बाजार अब उच्च नीतिगत दरों की नई वास्तविकता के अनुकूल है, रिज़र्व प्रबंधकों को निश्चित आय प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन नुकसान, अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजारों की पृष्ठभूमि में विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य को संरक्षित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वे अभी भी अपने पोर्टफोलियो पर उचित प्रतिलाभ की तलाश कर रहे हैं।

X.57 इस पृष्ठभूमि में, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) के प्रबंधन के लिए उस क्रम में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के व्यापक उद्देश्य के साथ काम करना जारी रखा। वर्ष दर वर्ष आधार पर 2022-23 के दौरान एफईआर में 4.8 फीसदी की कमी आई है, जबकि पिछले साल इसमें 5.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

X.58 अस्थिर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के प्रतिकूल वातावरण के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के कुशल प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, मंदी की चिंताओं, उच्च मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति को सख्त बनाने जैसी वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियों ने अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहारा प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने के साधन के रूप में रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण पर नए सिरे से जोर दिया गया है। तदनुसार, बढ़ी हुई प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका (*उत्कर्ष* 2.0 विजन) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, विभाग ने एसीयू में भुगतान और निपटान के लिए आईएनआर सहित घरेलू मुद्राओं [एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य राज्यों] के उपयोग तलाशने और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) को आईएनआर को नामित विदेशी मुद्रा का दर्जा देने में सक्षम बनाने जैसी नई पहल शुरू की। द्विपक्षीय व्यापारों के निपटान के साथ-साथ अन्य अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन के निपटान में घरेलू मुद्राओं के उपयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करके आईएनआर के और अंतरराष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

X.59 विभाग ने अपने निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) की तैनाती के लिए नए परिसंपत्ति के वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके भंडार के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा। विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो जैसे नए पेश किए गए उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया भी वर्ष के दौरान जारी रही।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.60 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए विभाग, एफसीए की सुरक्षा और चलनिधि सुनिश्चित करते हुए नए उत्पादों/अवसरों का पता लगाना जारी रखेगा (पैराग्राफ X 61)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से, विभाग ने कुछ अतिरिक्त बाजारों में निवेश करना शुरू कर दिया है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.62 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- अगली पीढ़ी के ट्रेजरी एप्लिकेशन (एनजीटीए) [उत्कर्ष 2.0] के कार्यान्वयन के द्वारा आरक्षित निधियों के प्रबंधन कार्यों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करना;
- विश्व स्तर पर आईएनआर की भूमिका को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की खोज के हिस्से के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक वातावरण का आकलन करने में विभाग की अनूठी स्थिति को देखते हुए, यह आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा, विभाग एसीयू तंत्र (उत्कर्ष 2.0) में आईएनआर और अन्य घरेलू मुद्राओं *के उपयोग को बढ़ावा* देगा; और
- सक्रिय रूप से विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना जारी रखना और आरक्षित निधियों के प्रबंधन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों को अपनाना।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.63 और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), रिज़र्व बैंक का ज्ञान केंद्र होने के नाते, नीति निर्माण और संचार के लिए विश्लेषणात्मक और अनुसंधान-आधारित इनपुट प्रदान करता है। विभाग (क) रिज़र्व बैंक के विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों को तैयार करने; (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक मदों पर प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह और द्वितीयक आंकड़ों का संकलन/प्रसार; (ग) अनुसंधान प्रकाशन जिसमें रिज़र्व बैंक के अनुसंधान और अन्य कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए कागजात/लेख शामिल हैं; (घ) बाहरी शोधकर्ताओं के साथ रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित अध्ययन जारी करना; (ङ) समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नीति निर्माण और तकनीकी समूहों/समितियों को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के कार्य में सम्मिलित है।

X.64 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और धन के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार आंकड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समय पर पूरा किया गया।

X.65 2022-23 में, विभाग ने कोविड-19 की तीसरी लहर के कम होने के बाद कार्यालय से काम करना जारी रखा और नीति निर्माण के लिए आवश्यक सभी विश्लेषणात्मक और अनुसंधान इनपुट समय पर प्रदान करना जारी रखा। विभाग ने सभी सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टों को समय पर जारी किया। वर्ष के दौरान तैयार और प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जबकि अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.66 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- हर साल कम से कम 100 शोध पत्र प्रकाशित करना और उभरते मुद्दों *(उत्कर्ष)* के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ X.67-X-69];
- नगरपालिका वित्त रिपोर्ट को समय पर बनाना और रिपोर्ट के कवरेज में सुधार करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ X.70];
- विभाग द्वारा [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] (केएलईएमएस) डेटासेट और मैनुअल का वार्षिक संकलन (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ X.71];
- समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए नई मशीन सीखने की तकनीकों का अनुप्रयोग (पैराग्राफ X.72); और

- पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग ढांचे में जलवायु जोखिम को शामिल करना और समष्टि-आर्थिक समुच्चय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना (पैराग्राफ X.72)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने अपनी प्रमुख वैधानिक रिपोर्ट, *अर्थात्*, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट को समय पर जारी किया। 'भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास' का पांचवां खंड जो 1997 से 2008 तक की 11 साल की अवधि को शामिल करता है, और 'राज्य वित्त: बजट का अध्ययन - 2022-23' नामक राज्य वित्त रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स - 2021-22' भी जारी किया गया। मुद्रा और वित्त 2022-23 पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसका विषय 'हरित स्वच्छ भारत की ओर' है।

X.68 विभाग ने वर्ष के दौरान 121 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए, जिनमें बाहरी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में 33 पत्र, आरबीआई वर्किंग पेपर्स में दस पेपर, आरबीआई सामयिक पेपर्स में आठ पेपर, दो डीआरजी स्टडीज और आरबीआई बुलेटिन में 68 लेख शामिल थे।

X.69 इन प्रकाशित शोध पत्रों/लेखों के भाग के रूप में सूचित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कई समकालीन मुद्दों को शामिल किया गया था, अर्थात् (क) भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की माप; (ख) भारत में असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए संयुक्त संयोग सूचकांक; (ग) भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई); (घ) मुद्रास्फीति अपेक्षाएं संचालित सूचकांक (आईईएआई); (ङ) समाचार आधारित भावना संकेतकों का उपयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना; (च) हरित सकल घरेलू उत्पाद का आकलन; (छ) भारत की प्राकृतिक ब्याज दर की समीक्षा करना; (ज) पूर्वोत्तर में सूक्ष्म वित्त के माध्यम से वित्तीय समावेशन; (झ) उत्पादकता आधारित विकास के लिए भारत का नवान्वेषण पारितंत्र; (ञ) तटीय राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव; (ट) सहकारी बैंकों में डिजिटलीकरण; (1) औद्योगिक क्रांति 4.0; और (ङ) भारत के विनिर्माण क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अपघटन का विश्लेषण।

X.70 वर्ष के दौरान, विभाग ने 'नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट' के प्रकाशन के माध्यम से नगरपालिका वित्त में एक अनूठा कार्य शुरू किया। रिपोर्ट को 'नगर निगमों के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत' पर आधारित किया गया था और सभी राज्यों को कवर करने वाले 201 नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों का उपयोग किया गया।

X.71 विभाग ने वर्ष के दौरान केएलईएमएस डेटा का स्वतंत्र संकलन पूरा किया और अक्टूबर 2022 में बैंक की वेबसाइट पर मैनुअल के साथ आंकड़े जारी किए।

X.72 वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने पर्यवेक्षित पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करके वित्तीय बाजार के आंकड़ों के आधार पर मुद्रास्फीति का नाउकास्टिंग किया और हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के प्रत्यक्ष और कैस्केडिंग प्रभावों को निर्धारित करने के लिए पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग फ्रेमवर्क में जलवायु जोखिम को शामिल करने पर काम किया। इसके अलावा, (क) मैक्रो-इकोनॉमिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों पर आधारित अध्ययन; (ख) वर्ष के दौरान भारतीय कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संबंधी अध्ययन किए गए।

अन्य पहल

X.73 वर्ष के दौरान, डीईपीआर स्टडी सर्कल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने विभिन्न विषयों पर शोध पत्रों के 38 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतियों का आयोजन किया। विभाग ने नवंबर 2022 में हैदराबाद में अपने वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें महामारी के बाद की अवधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के अर्थशास्त्र जैसे सामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

X.74 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने तीन नए ऑनलाइन डेटाबेस की सदस्यता ली और अनुसंधान करने के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा प्रदान की। वर्ष के दौरान, आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से 210 फाइलें प्राप्त कीं। वर्ष के दौरान लगभग पांच लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.75 वर्ष 2023-24 के लिए विभाग का कार्ययोजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होगा:

- कम से कम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन और उभरते मुद्दों के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना *(उत्कर्ष* 2.0*);*
- स्पिलओवर को मापने के लिए सूचकांकों के साथ 'वैश्विक मौद्रिक नीति और वैश्विक स्पिलओवर डैशबोर्ड' का विकास *(उत्कर्ष* 2.0*);*
- 'वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी फ्रेमवर्क (ग्लोबल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) का विकास *(उत्कर्ष* 2.0*);* और
- वर्ष के दौरान नीतिगत प्रासंगिकता वाले विभिन्न सामयिक मुद्दों पर अध्ययन किए जाएंगे।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.76 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने नई प्रौद्योगिकी-सक्षम उपकरणों को तैनात करके समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को समेकित किया, और नीति निर्माण के लिए उद्यम और घरेलू सर्वेक्षण, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के माध्यम से सांख्यिकीय सहायता प्रदान की और रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यों में भी सहायता की। प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में वर्षों से निवेश, जिसमें डेटा रिपोर्टिंग संस्थाओं की हैंड-होल्डिंग और अन्य मार्गदर्शन शामिल हैं, व्यवधानों की अवधि में डेटा की निरंतरता और शोधन प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में रहे। । महामारी के बाद से विकसित गतिशीलता ने सूचित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है और विभाग ने पारंपरिक विश्लेषण के पूरक के लिए असंरचित/गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का विश्लेषण करने में बिग डेटा/ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग किया है। अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस के चुनिंदा मॉड्यूल [*यानी*, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] को समानांतर रन के लिए भी जारी किया गया था।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.77 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उन्नत विश्लेषिकी वातावरण में सभी प्रकार के एकीकरण को पूरा करना और अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस (*उत्कर्ष*) में सभी नियमित डेटा प्रकाशनों के प्रकाशन कार्यप्रवाह को स्वचालित करना [पैराग्राफ X.78];
- एससीबी से शुरू करते हुए चरणबद्ध तरीके से व्यापक क्रेडिट सूचना भंडार को लोकप्रिय बनाना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ X.79];
- एक लचीले तत्व-आधारित रिपॉजिटरी (ईबीआर) के माध्यम से नए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन, जिसमें पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिटर्न-आधारित रिपॉजिटरी (आरबीआर) से परिवर्तित करने की सुविधा है (पैराग्राफ X.80);
- रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाए रखना जो रिज़र्व बैंक को डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में और सुधार के लिए बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग

संस्थाओं की सहायता के लिए सभी संसाधन और सत्यापन नियम प्रदान करता है (पैराग्राफ X.81);

- सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों के लिए अनुमान प्रक्रियाओं का और परिष्करण [पैराग्राफ X.82]; और
- रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग (पैराग्राफ X.83)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.78 सीआईएमएस कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, उन्नत विश्लेषिकी परिवेश के सभी घटक परीक्षण के अधीन हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। सभी नियमित प्रकाशनों के लिए प्रकाशन कार्यप्रवाह का स्वचालन भी परीक्षण चरण में पहुंच गया है।

X.78 व्यापक ऋण सूचना भंडार (सीसीआईआर) के लिए एप्लिकेशन विकसित की जा रही है। परीक्षण पूरा होने और चुनिंदा एससीबी के साथ एक प्रायोगिक आधार पर शुरू होने के बाद, रिपॉजिटरी लाइव हो जाएगी।

X.80 रिटर्न आधारित रिपॉजिटरी (आरबीआर) से तत्व-आधारित रिपॉजिटरी (ईबीआर) में डेटा को परिवर्तित करने के लिए एक कनवर्टर टूल विकसित किया गया है और प्रमुख पर्यवेक्षी रिटर्न के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और अधिक आइटम जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) तत्वों के लिए आरबीआर मैपिंग के लिए सारणियों को पर्याप्त संख्या में रिटर्न के साथ-साथ गैर-रिटर्न डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

X.81 वेबसाइट पर 'विनियामक रिपोर्टिंग' टैब को संशोधित किया गया है और विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एफएक्यू, मैनुअल, मार्गदर्शन नोट्स और सत्यापन नियमों के साथ जोड़ा गया है।

X.82 सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में नियमित सर्वेक्षणों से सुदृढ़ आकलन के लिए डेटा गुणवत्ता और संकलन पद्धतियों को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल थे: (ए) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर घरेलू सर्वेक्षण शुरू करना; (ख) सेवा और अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) में अवसंरचना परियोजनाओं और रियल एस्टेट संपदा कार्यकलापों में लगी निर्माण कंपनियों की भावनाओं को अलग से दर्शाना।

X.83 विश्लेषणात्मक कार्य में, बिग डेटा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और एमएल तकनीकों का उपयोग बढ़ गया, और डेटा के वैकल्पिक स्रोतों का भी उपयोग किया गया। इनमें समष्टि-आर्थिक चरों (मैक्रोइकॉनॉमिक वेरिएबल्स) पर मीडिया की भावनाओं, खाद्य और आवास की ऑनलाइन कीमतें, केंद्रीय बैंक के संचार के साथ-साथ भुगतान प्रणाली संकेतकों और प्रगामी सर्वेक्षणों (फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वे) का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक पूर्वानुमान शामिल थे। रिमोट सेंसिंग परियोजनाओं का दायरा अधिक संवेदनशील कृषि वस्तुओं [*जैसे* दालों, तिलहनों, प्याज और गेहूं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बास्केट में महत्वपूर्ण भारांक रखने वाले] को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था, जिसमें कई संकेतक (जैसे वनस्पति, वर्षा, मिट्टी की नमी, तापमान और वैश्विक जलवायु कारक, जैसे, समुद्र की सतह का तापमान और समुद्र स्तर का दबाव) शामिल थे।

अन्य पहल

X.84 पिछले पांच दशकों से भारतीय बैंकिंग के वितरण पहलु प्रदान करने वाली मूलभूत सांख्यिकी विवरणी (बीएसआर) प्रणाली पर अक्टूबर-नवंबर 2022 के दौरान आयोजित दो सम्मेलनों में पुनः विचार किया गया, इसमें बैंकरों और अन्य विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। विचार-विमर्श के आधार पर, बीएसआर -1 (क्रेडिट का विवरण) और बीएसआर -2 (जमा का विवरण) विवरणी की आवृत्तियों को समन्वित किया जा रहा है, और बीएसआर -7 रिटर्न को दिसंबर 2022 के बाद बंद कर दिया

बॉक्स X.4
मूल सांख्यिकीय विवरणियां @ 50 वर्ष

बीएसआर प्रणाली को 1972 में बैंकिंग सांख्यिकी समिति की सिफारिश पर इस तरह से तैयार किया गया था कि यह न केवल नीतिगत निर्णयों और बैंकों से सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के साथ विस्तृत निगरानी की आवश्यकता को पूरा करती है, बल्कि बैंकों के लिए रिपोर्टिंग बोझ को भी कम करती है। इसके बाद, बीएसआर प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए बैंकिंग सांख्यिकी पर निदेश समिति (सीडीबीएस) का गठन किया गया था, जिसमें बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों के अलावा रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

बीएसआर प्रणाली ने 2022 में सफलतापूर्वक संचालन के पचास साल पूरे किए। पचास वर्षों के दौरान, बैंकिंग बुनियादी ढांचे के विवरण के साथ प्रणाली ने सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए। इसने आर्थिक क्षेत्र, भूगोल, संस्थानों, व्यवसायों, बैंक समूहों और ऋण तथा जमा के प्रकार सहित कई महत्वपूर्ण कारकों पर व्यापक आंकड़े प्रदान किए। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, और वे सभी बैंकिंग प्रणाली में रिज़र्व बैंक के प्रतिबद्ध भागीदार बने हुए हैं।

पचास साल की यात्रा के समापन का जश्न मनाने और आगे के राह पर विचार करने के लिए 28 अक्टूबर, 2022 को मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में और 4 नवंबर, 2022 को गुवाहाटी में भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) में दो सम्मेलन आयोजित किए गए थे। सम्मेलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल थे:

1. मूल सांख्यिकीय विवरणियों की दृष्टि के माध्यम से भारतीय बैंकिंग के पचास साल, उप गवर्नर डॉ माइकल देवव्रत पात्र द्वारा दिया गया भाषण;
2. बीएसआर की 50 साल की यात्रा (1972-2022): एक प्रस्तुति;
3. ज्ञान साझा करना - बैंकिंग आंकड़ों का उपयोग करते हुए पांच शोध लेखों की प्रस्तुति; और
4. बीएसआर में आगे की राह - अगले साल से प्रणाली में लागू होने वाले बड़े परिवर्तनों पर चर्चा।

प्रणाली में आनेवाले प्रमुख परिवर्तन जिन पर ज़ोर दिया गया था वे हैं :

1. तिमाही बीएसआर -7 रिपोर्टिंग को बंद करना;
2. तिमाही आवृत्ति के साथ बीएसआर -2 जारी करना; और
3. बीएसआर -2 में व्यक्तियों और महिलाओं के स्वामित्व वाली जमा राशियों के आयु-वार वितरण पर अतिरिक्त जानकारी का संग्रह।

संदर्भ:

1. पात्रा माइकल डी.(2022), 'फिफ़्टी ईयर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग थ्रू दी लेंस ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न', आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2022।
2. रंगराजन सी.(2008), 'वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट'।
3. आरबीआई (2022), 'बीएसआर@50 स्मारक खंड (1972-2022)'।
4. आरबीआई (1972), 'बैंकिंग सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री ए रमन)'।

स्रोत: आरबीआई।

गया है। इस अवसर पर, बीएसआर और बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई: पूर्ववर्ती मास्टर ऑफिस फाइल) के 50 साल के इतिहास के साथ-साथ बीएसआर डेटा के आधार पर चुनिंदा शोध कार्यों को शामिल करते हुए एक स्मारक खंड 'BSR@50' भी जारी किया गया (बॉक्स X.4)।

X.85 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में कार्य करने वाले बैंकों की शाखाओं और सहायक कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन को कवर करने के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़ों को पूरा करने के लिए सूचना स्रोतों का विस्तार किया गया था। भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक जनगणना के कवरेज में भी सुधार हुआ है। सभी नियमित बैंकिंग और बाहरी क्षेत्र के सर्वेक्षणों के प्रकाशन अंतराल को बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं के निरंतर प्रयासों और हैंडहोल्डिंग के साथ कम कर दिया गया था।

X.86 कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों ने विश्लेषण के लिए पद्धतियों में उपयुक्त समायोजन और महत्वपूर्ण समष्टि-आर्थिक चरों का विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए आउटपुट और मूल्य संकेतकों के मौसमी व्यवहार के आकलन के लिए पद्धतिगत सुधार किए गए थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.87 विभाग 2023-24 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- अत्याधुनिक डेटा पोर्टल में उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण का निर्माण करना और उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित डैशबोर्ड बनाना *(उत्कर्ष* 2.0*);*
- सीआईएमएस के शेष मॉड्यूलों को कार्यान्वित करना, प्रश्न और दृश्य टूल (क्वेरी और विज़ुअलाइज़ेशन टूल) प्रदान करना, सभी विनियमित संस्थाओं को इस पर लाना, और पुरानी प्रणालियों [केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल] को निष्क्रिय करना;
- रिज़र्व बैंक के नियमित घरेलू सर्वेक्षणों का ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार करना *(उत्कर्ष* 2.0*);*
- एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग विवरणियों के लिए डेटा गुणवत्ता को और बेहतर बनाना *(उत्कर्ष* 2.0*);* और
- गैर-पारंपरिक आंकड़ों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के अतिरिक्त उच्च आवृत्ति संकेतकों का निर्माण करना।

8. विधिक मुद्दे

X.88 कानूनी विभाग एक सलाहकार विभाग है जो कानूनी मुद्दों की जांच करने और सलाह देने और रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमेबाजी के प्रबंधन की सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया है। विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के लिए परिपत्रों, निदेशों, विनियमों और समझौतों का पुनरीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिज़र्व बैंक के निर्णय कानूनी रूप से सही हैं। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है और परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र (सीएएफआरएएल) और आरबीआई के स्वामित्व वाले अन्य संस्थानों को कानूनी मुद्दों, मुकदमेबाजी और अदालती मामलों पर कानूनी समर्थन और सलाह भी देता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.89 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यप्रवाह स्वचालन प्रक्रिया एप्लिकेशन के कार्यान्वयन को पूरा करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ X.90] ;
- मौजूदा ओपिनियन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली का विलय करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ X.90]; और
- उपलब्ध/मौजूदा कानूनी अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रयोक्ताओं को उनकी पहुंच प्रदान करना (पैराग्राफ X.91)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.90 कार्यप्रवाह स्वचालन प्रक्रिया एप्लिकेशन, जो विधि विभाग की मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (सीएएमएस) है, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा विकसित किया गया है। यह आवेदन मौजूदा ओपिनियन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एप्लिकेशन का प्रायोगिक आधार पर परीक्षण किया गया है। प्रायोगिक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया को एप्लिकेशन में एकीकृत किया गया है। तीन मॉड्यूल वाले एप्लिकेशन का पहला चरण लाइव हो गया है।

X.91 उपलब्ध कानूनी अभिलेखों का डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

अन्य गतिविधियां

X.92 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधान/विनियम इस वर्ष के दौरान लाए गए/संशोधित किए गए :

- *भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन:* वित्त अधिनियम, 2022 ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 में 'बैंक नोट' की परिभाषा जोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया। इससे रिज़र्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल मुद्रा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- *क्रेडिट सूचना कंपनियों को आरबीआईओएस 2021 के दायरे में लाना:* रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबीआईओएस), 2021 को संशोधित किया गया है कि जिससे कि क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित 'क्रेडिट सूचना कंपनी' को इस प्रयोजन के लिए 'विनियमित इकाई' के रूप में को शामिल किया जा सके है। परिणामस्वरूप, यह योजना क्रेडिट सूचना कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होगी, जिस सीमा तक इसे योजना के तहत विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया है। इस योजना में संशोधन 1 सितंबर, 2022 से लागू हो गया है।
- *विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का संशोधन*: केंद्र सरकार ने प्रमुख नियमों, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2022 बनाए हैं। यह संशोधन 12 अप्रैल, 2022 से लागू हो गया है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.93 2023-24 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मामला प्रबंधन प्रणाली (सीएएमएस) को सीएएमएस 2.0 में अपग्रेड करना जिससे कि: (ए) वास्तविक समय पर मामले की स्थिति के लिए बाहरी न्यायिक वेबसाइटों के साथ एकीकरण किया जा सके; और (बी) इंटरनेट पर सीएएमएस तक पहुंच जिससे कि 'कहीं से भी कार्य' मोड *की सुविधा प्रदान की जा सके (उत्कर्ष* 2.0);
- रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए विधिक विभाग के मैनुअल का मसौदा तैयार कर इसे प्रकाशित करना *(उत्कर्ष* 2.0*);* और
- उपलब्ध/मौजूदा कानूनी अभिलेखों के डिजिटलीकरण को जारी रखना और उनकी पहुंच उपलब्ध कराना।

9. निष्कर्ष

X.94 रिज़र्व बैंक की संचार कार्यनीति और मौखिक और अनौपचारिक संचार इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संरचित और लिखित संचार को तेजी से पूरक कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को प्रकट करने, सार्वजनिक हित के नीतिगत कार्यों को अनौपचारिक और शिक्षाप्रद प्रारूप में संप्रेषित करने के लिए अपने 360 डिग्री अखिल भारतीय जन जागरूकता अभियानों का भी उपयोग किया, जिसका लक्ष्य जनता के साथ अधिक जुड़ाव बढ़ाना है। रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता संभाली है, और रिज़र्व बैंक दिसंबर 2023 से एक वर्ष के लिए एसईएसीईएन केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नीति निर्माण और संचार के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक और अनुसंधान इनपुट को समय पर पूरा किया गया और वैधानिक और गैर-वैधानिक प्रकाशनों ने समकालीन नीति और कार्यनीतिक मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला पर बैंक में किए गए अनुसंधान कार्यों का प्रसार किया। रिज़र्व बैंक में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन ने नई प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों को तैनात करके समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को समेकित किया और नीति निर्माण के लिए उद्यम सर्वेक्षण, आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषणात्मक इनपुट के माध्यम से सांख्यिकीय सहायता प्रदान की।